मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता ! दुनिया के मजदूरों, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है । दुनिया को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233

नई सीरीज नम्बर 6 दिसम्बर 1988 50 पैसे

मानव समाज

रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा मानव जीवन की बुनियादी जरूरत हैं । जब तक इनकी कमी रहती है तब तक इन्हें हासिल करना समाज की धुंरी (एक्सल) होती है । अब तक हमने रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा की तंगी वाले हालात ही झेले हैं। इसलिये अपनी इन बुनियादी जरूरतों को हम किस तरह पूरा करने के प्रयास करते रहे हैं इस चीज ने मानव समाज के अलग-अलग ढाँचों को जन्म दिया है ।

जंगली जानवरों से सुरक्षा, कन्द-मूल बटोरने और शिकार करने की बहुत लम्बे समय तक हावी रही हालात में मानव समाज का संगठन बराबरी और मिलजुल कर काम करने वालों का था । इसे आदिम साम्यवादी संगठन कहते हैं ।

अपनी बुनियादी जरूरतों के लिये संघर्ष कर रहे हमारे उन पुरखों ने अन्य कामों के साथ ही पशुपालन सीखा । अपनी लागत से ज्यादा पैदा करने की राह पर मेहनती मानव ने यह एक बड़ा कदम उठाया था। पशुपालन ने सामाजिक ढाँचों में क्रान्ति ला दी । मिल-जुलकर काम करने और बाँटकर खाने वाला सामाजिक ढाँचा टूट गया। मानव समाज बँट गया । बँटवारा एक लम्बी प्रक्रिया की उपज है ।

स्वामी और दास—यह था मानव समाज का पहला ज्ञात बंटवारा । स्वामियों के लिये अच्छी रोटी, अच्छे कपड़ों और अच्छे मकानों की व्यवस्था दासों को करनी पड़ती थी । ऊपर से स्वामियों की सेवा भी दासों के मत्थे थी। साफ बात है, जंगली जानवरों की बजाय स्वामियों को मुख्य खतरा दासों से था । इसलिये शस्त्र और शास्त्र पर स्वामियों ने कब्जा किया । अपनी सुरक्षा और हरामखोरी के लिये स्वामियों ने पुलिस, फौज, जेल, कोर्ट, धर्मगुरु और प्रोफेसर बनाये । बाद के लुटेरों ने अपने इन हथियारों में चार चाँद लगाये हैं ।

धुरी में आये बदलाव ने समाज में वह भूचाल लाया कि स्वामियों के सब शस्त्र और शास्त्र धरे रह गये । लोहे की जानकारी ने पशुपालन की जगह खेती को समाज का मुख्य काम बनाया । मानव समाज बँटा ही रहा पर दूसरी लुटेरी व्यवस्था का जन्म हुआ—स्वामियों का स्थान सामन्तों ने ग्रहण किया । टांकेदारों-जागीरदारों-राजाओं-महाराजाओं ने मेहनत-मशक्कत करने वाले अर्ध-दासों के खिलाफ अपने शस्त्र तथा शास्त्र और पैने किये ।

समाज की धुरी में आये नये बदलाव से पैदा हुई उथल-पुथल के सामने सामन्तों के पैने हथियार भी धरे रह गये । राजा-नवाबों और उनके लगुओं-भगुओं के खान-पान के लिये पैदावार के साथ-साथ सामन्तों की फौज और शान-शौकत की जरूरतों ने सामन्तवाद में मंडी के लिये उत्पादन को बढ़ाया । इस बढ़ते माल उत्पादन ने सामन्तों की चपटी धरती को गोल सिद्ध कर दिया । व्यापारियों ने दुनिया को एक सूत्र में पिरो दिया ।

छल-कपट में माहिर व्यापारी ज्यादा दिन अपना दबदबा कायम नहीं रख सके । समाज की धुरी में एक बड़ा बदलाव आया था । खेती-दस्तकारी के मुख्य धन्धों का स्थान भाप-कोयला-मशीनरी के बवंडर ने फैक्ट्रीयों को सौंपा । इस तरह हजारों साल पहले मानव समाज में जो बँटवारा हुआ था वह अपनी आखिरी मंजिल में दाखिल हुआ। तब से एक तरफ हैं समाज के पैदावार के साधनों पर काबिज पूंजी के नुमाइन्दे और दूसरी तरफ हैं जिन्दा रहने के लिये अपनी मेहनत बेचने को मजबूर मजदूर । दो-ढाई सौ साल पहले शुरू हुआ मानव समाज का यह नया बँटवारा आज दुनिया-भर में मुख्य चीज बन गया है। बढ़ रहे हैं दुनिया में मजदूरों के संघर्ष और पैने कर रहे हैं पूंजी के नुमाइन्दे अपने शस्त्र व शास्त्र ।

रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा की कमी अब मानव समाज की मजबूरी नहीं है । इसलिये समाज की नई धुरी के निर्माण का समय आ गया है । इस नई धुरी की खासियत मानव की बुनियादी जरूरतों की कमी नहीं बल्कि उनकी बहुतायत होगी । नये किस्म के मिल-जुलकर काम करने और बाँटकर खाने के सामाजिक संगठन की ठोस हालात पैदा हो गई हैं । और वैसा समाज बनाने की जिम्मेदारी इतिहास ने मजदूर वर्ग के कन्धों पर डाली है क्योंकि समाज की नई धुरी के निर्माण का सवाल कारखानों से ही उठेगा । मजदूरों की मुक्ति नये साम्यवादी समाज के लिये संघर्ष में है । और यही सम्पूर्ण मानव समाज की मुक्ति की राह है ।

दुनिया में मजदूरों के संघर्ष

पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ते संकट की वजह से भड़कते असन्तोष को काबू में रखने के लिये कुछ समय पहले तक सख्ती और फौजी शासन लागू करना दुनिया में आम रुझान था । और अब सख्ती में पल रहे खतरों से घबराकर दुनिया-भर में पूंजी के नुमाइन्दे नरमी-खुलेपन-जनतन्त्र के फैशन को अपना रहे हैं। जनतन्त्रों में सख्ती और सख्ती वाले इलाकों में जनतन्त्र के आम रुझान से इस समय दुनिया-भर में एक जैसी कड़वी खिचड़ी पक रही है फिलिपीन में चुनाव, चीन में नरमी, रूस में खुलापन, ब्राजिल में जनतन्त्र, पाकिस्तान में चुनाव पूंजीवादी व्यवस्था के संकट को दूर नहीं कर सकते । यह टूटे झुनझुने हैं, यह ज्यादा दिन नहीं बजेंगे । ईरान, बर्मा और पौलैंड जैसी हालात बनने के आम आसार ही ज्यादा हैं पर दुनिया-भर में मजदूरों के बढ़ते संघर्ष मुक्ति की छलाँगों, मजदूर क्रान्तियों की लहर की सम्भावना को बढ़ा रहे हैं ।

ऐसा ही एक संघर्ष इस समय ब्राजिल के मजदूर कर रहे हैं । ब्राजिल दक्षिणी अमरीका में एक बड़ा देश है । भारत की ही तरह यह एक कमजोर पूंजी वाला देश है । इसलिये पूंजीवाद का गहराता संकट ब्राजिल में भी तीखी उथल-पुथल पैदा कर रहा है । 12 नवम्बर का नवभारत टाइम्स देखिये : ब्राजिल के सबसे बड़े इस्पात कारखाने में हड़ताल तोड़ने के लिये सेना घुस गई और तब मजदूरों और सैनिकों के बीच आमने-सामने लड़ाई हुई । वोल्टा रेजेंडा शहर के इस कारखाने में 20 हजार मजदूर हड़ताल पर हैं । फौज के 700 जवान कारखाने में घुस गये और दरवाजे पर उन्होंने टैंक अड़ा दिये । तब मजदूर भी उन पर टूट पड़े ।

पुलिस को तो यहाँ भी मजदूर हर रोज मैनेजमेंट के हथियार के तौर पर देखते ही हैं, ब्राजिल की घटना साफ-साफ दिखाती है कि जब हालत पुलिस के काबू से बाहर हो जाती है तब फौज का असली चेहरा भी सामने आ जाता है । हर देश में फौज वहाँ पूंजी के नुमाइन्दों का मजदूरों के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है । भारतीय फौज आज आस-पास के विरोधी छुटभैया पूंजीवादी देशों को आँखें दिखाने और "भारतीय" पूंजी के पिठ्ठुओं को टिकाये रखने के लिये खून-खराबा कर रही है । लेकिन भारतीय फौज के असली निशाने संघर्ष में उठने वाले मजदूर ही होंगे ।

ब्राजिल के मजदूरों के संघर्ष के बारे में 13 नवम्बर का नवभारत टाइम्स भी देखें : ब्राजिल में जो हड़ताल इस्पात कारखाने में चल रही थी, उसके अब तेल रिफाइनरी तक पहुँचने के आसार हैं । तेल रिफाइनरी के 60 हजार मजदूरों ने नोटिस दे दिया है ।

यहाँ फिर हम लोगों के लिये सबक है । आज कारखानों में लगी पूंजी एक या चन्द लोगों की नहीं है । मैनेजमेंटों द्वारा चलाये जा रहे ज्यादातर कारखानों में पैसे बैंकों, बीमा या छोटे-छोटे शेयर होल्डरों के लगे हैं । पहले एक-दो मालिक होते थे और तब लम्बी हड़ताल से उनका भट्टा बैठाने की सम्भावना थी पर आज के हालात में एक कारखाने में लम्बी हड़ताल से मैनेजमेंट को ज्यादा चोट नहीं लगती । बल्कि, लम्बी हड़ताल में मजदूरों की ताकत कम होती जाती है । नई हालात में संघर्ष का तेजी से फैलना और तीखा होना मजदूरों के संघर्ष की राह है । हड़ताल कर रहे मजदूरों को समर्थन का अब मतलब हड़ताल में शामिल होना है—समर्थन प्रस्तावों, भाषणों, चन्दा, महीनों बाद एक-दो दिन की समर्थन में हड़ताल अब बीते समय की रस्म दोहराना मात्र रह गया है ।

और अन्त में देखिये 14 नवम्बर का पंजाब केसरी : ब्राजिल में भूख से पीड़ित 300 से अधिक लोगों ने दो सुपर बाजारों को लूट लिया । गन्दी बस्ती में रहने वाले इन लोगों को भगाने के लिये पुलिस ने हवा में गोलियाँ चलाईं और उनका पीछा किया पर वे चावल, दालें, मांस और अन्य सामान लेकर चम्पत हो गये । सुपर मार्किट मैनेजर ने कहा कि धावा बोलने वाले अधिकतर नंगे पाँव और अर्ध-नग्न थे । लगता था कि इन लोगों ने भूख से पीड़ित होने के कारण ऐसा किया ।

भूखे मरतों के सामने और क्या रास्ता है ? ब्राजिल जैसे ही हालात भारत में हैं । मजदूरों का क्रान्तिकारी संघर्ष ही भूखे-नंगों को आज सब मेहनतकशों के दुख-दर्द की जड़ दिखा सकता है और उनकी अथाह शक्ति को उसे उखाड़ने में लगा सकता है । भारत में मजदूर-वर्ग का क्रान्तिकारी संघर्ष समय की माँग है । आओ इसे पूरा करें ।

बाटानगर तालाबन्दी

भारत में बाटा की मुख्य फैक्ट्री बाटानगर (बंगाल) में है । 9 जुलाई 88 को मैनेजमेंट ने वहाँ तालाबन्दी की । इसकी मुख्य वजह पूंजीवादी व्यवस्था का बढ़ता संकट है जिसने आज हर मैनेजमेंट को परेशानी में डाला हुआ है । इस संकट और परेशानी का इलाज पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं हो सकता फिर भी साम-दाम-दंड-भेद के जरिये मैनेजमेंटें पूंजीवाद के संकट के बोझे को मजदूरों के मत्थे मढ़ने की कोशिशों में हर समय लगी रहती हैं । और अपने सत्ता-बल पर मैनेजमेंटें जगह-जगह मजदूरों को बलि के बकरे बना रही हैं । फिर भी संकट गहराता जा रहा है क्योंकि संकट पूंजीवादी व्यवस्था का है । इसका इलाज मजदूर क्रान्तियों द्वारा पूंजीवाद को दफनाने में ही है ।

लेकिन और मैनेजमेंटों की तरह ही बाटा मैनेजमेंट भी छः इन्च से दूर नहीं देख सकती । इसलिए छंटनी करना, वर्क लोड बढ़ाना और सस्ते में फैक्ट्री से बाहर ठेके पर काम करवाना अन्य मैनेजमेंटों की ही तरह इस समय बाटा मैनेजमेंट की भी मुख्य पालिसी है । इस पालिसी को लागू करने के लिये मजदूरों को झुकाना जरूरी है—इसीलिये मैनेजमेंट ने बाटानगर में तालाबन्दी की । चार महीने तालाबन्दी से अपनी सब शर्तें मनवाकर मैनेजमेंट ने 10 नवम्बर से फैक्ट्री खोल दी है ।

कलकत्ता के बांगला दैनिक 'आजकाल' ने बाटा मैनेजमेंट-यूनियन समझौते के समाचार 7 नवम्बर को छापे : एक तरफ तो बंगाल सरकार ने 12 जुलाई को ही तालाबन्दी को गैरकानूनी घोषित कर दिया था और दूसरी तरफ बंगाल सरकार के ही लेबर सैकरेट्री ने 4 नवम्बर को राज्य-सचिवालय में कहा, "बाटा मैनेजमेंट धमकी दे रही है । राज्य सरकार असहाय है । आप लोग द्विपक्षीय बातचीत कीजिये । मैनेजमेंट

के प्रस्ताव मान लेना ही अच्छा है।" मैनेजमेंट की सब शर्तों (74) पर यूनियन ने दस्तखत कर दिये हैं। एग्रीमेंट के मुताबिक कई डिपार्टमेंटों को खत्म किया जायेगा, कम्प्यूटर लगेंगे, वर्क लोड बढ़ेगा, फैक्ट्री से बाहर ठेके पर काम होगा और मजदूरों के लिये जो सुविधायें अब तक थीं वे कम की जायेंगी। सरकार द्वारा घोषित गैरक़ानूनी तालाबन्दी का पैसा मजदूरों को नहीं मिलेगा। कानून-वानून के चक्कर में पड़ने वाले मजदूरों को इससे कुछ सीखना चाहिये। बाटानगर तालाबन्दी से मजदूरों को यह भी सीखना चाहिये कि इस व्यवस्था में कुरसी पर बैठने वालों को बदलने से मजदूरों को असल में कुछ नहीं मिलता।

एक फैक्ट्री के मजदूरों पर मैनेजमेंट के हमले के समय आस-पास की फैक्ट्रियों के मजदूर अपने साथी मजदूरों के समर्थन में कम ही कदम उठाते हैं जबकि मैनेजमेंट-लेबर डिपार्टमेंट-पुलिस-प्रशासन-सरकार वाला पूंजीवादी धड़ा आमतौर पर एक होकर काम करता है। बाटा की फैक्ट्रियों में तो हालत और भी खराब है। जब बाटा-फरीदाबाद में मजदूरों को दबाने के लिये मैनेजमेंट फ़ैक्ट्री बन्द करती है तब बाटा-नगर, मोकामा, दीघाघाट की बाटा फैक्ट्रियों में ओवरटाइम काम मैनेजमेंट को मजबूत करता है। और जब बाटानगर में मैनेजमेंट तालाबन्दी करती है तब फरीदाबाद, मोकामा, दीघाघाट की बाटा फैक्ट्रियों में मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिये ओवर-टाइम काम होता है। इसकी मुख्य वजह है मजदूरों के अगुआ बने लोगों का मैनेजमेंट की जेब में होना। इन लोगों की हरकतों से बाटा फरीदाबाद का आम मजदूर बाटा-नगर के आम मजदूर के खिलाफ हो जाता है और बाटानगर का आम मजदूर फरीदाबाद के आम मजदूर के खिलाफ। पहले किसने क्या किया की बहसें मजदूरों की फूट को गहरा करती हैं। इस घातक जकड़ को तोड़ने के लिये बाटा फरीदाबाद के कुछ मजदूरों द्वारा बाटानगर तालाबन्दी के खिलाफ में ओवरटाइम न करना एक अच्छा कदम है। पूंजीवादी व्यवस्था के कर्त्ताधर्त्ताओं के खिलाफ मजदूरों द्वारा मिल कर संघर्ष करना जरूरी है। मजदूरों का नारा है : एक पर हमला, सब पर हमला !

बाटानगर में मजदूरों के खिलाफ उठे कदमों को फरीदाबाद पहुँचने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे।

सोवरिन निट वर्क्स के मजदूरों का खत

मैसर्ज सोवरिन निट वर्क्स के प्रबन्धकों द्वारा धाँधलेबाजी के कारण सभी श्रमिकगण परेशान हैं। 21-7-88 से डाइंग खाते में गैरकानूनी ले आफ कर रखी है और डाइंग खाते के श्रमिकों को पिछले 2 महीने का अर्जित वेतन नहीं दिया गया है। वेतन से E. S. I. काटी जाती है लेकिन सम्बन्धित खाते में जमा नहीं करवाई जाती है। श्रमिकों के वेतन से P. F. की कटौती की जाती है लेकिन पिछले 3 वर्षों से P. F. के संबंधित खाते में कोई पैसा जमा नहीं करवाया गया। ओवरटाइम सिंगल दिया जाता है और सरकार को दिखाने के लिये ओवरटाइम के रिकार्ड में डबल भरा जाता है। अभी वेतन सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को नहीं दिया जाता। गैरकानूनी कम्पनी को बन्द दिखाकर श्रमिकों के वेतन से गलत कटौती की जाती है। जब हम वेतन ना देने के केस को पेमेन्ट आफ वेजिज एक्ट में ले जाते हैं तो फैक्ट्री की ओर से कोई आदमी हाजिर नहीं होता। एक तरफा फैसले किये जाते हैं। लाखों रुपये के केस की डिग्री हो चुकी है तथा C J. M. के कोर्ट में रिकवरी के लिये पहुँच चुकी है लेकिन आज तक कोई रिकवरी नहीं की गई। P. F. कमिश्नर को यूनियन के प्रति-निधि ने अनेकों पत्र लिखे हैं लेकिन आज तक P. F. की कोई रकम जमा नहीं की गई है। मालिकान दिल्ली में बैठे हैं तथा उनके लड़के और घरवाली फैक्ट्री में आते-जाते रहते हैं। कम्पनी में मालिकान द्वारा बैठाये गये जिम्मेदार आदमी सरकार के किसी भी नोटिस को नहीं लेते हैं। यूनियन के प्रतिनिधियों ने 15-11-88 को जोइन्ट लेबर कमिश्नर श्री धर्मेन्द्र नाथ से बातचीत की और उद्योग की सारी समस्या उन्हें बताई तो श्री नाथ साहब ने कहा कि वो तो पुराने बदमाश हैं, उनको तो आप खुद पकड़ो। श्रम आयुक्त हरियाणा सरकार के ये शब्द हैं तो बताओ श्रमिकों का क्या होगा। श्री नाथ की इन बातों का जवाब यूनियन के प्रतिनिधियों ने बड़े दुख के साथ दिया और कहा कि जब श्रमिक की रक्षा करने वाले साहब इस तरह की बातें करते हैं तो हम गरीब मजदूरों का क्या हाल होगा। C. J. M. के नोटिस को लेने से इनकार किया जाता है और सिविल कोर्ट की तिथि पर नहीं पहुँचते हैं। हमने यूनियन के लैटर हैड पर मालिकान के पते पर भेजे हैं। बड़े खेद का विषय है कि मजदूर कांग्रेस की सरकार को गलत बताते थे लेकिन लोकदल की सरकार क्या ठीक है। हम तो यह समझते हैं कि ना कांग्रेस की सरकार ठीक है ना लोकदल की सरकार ठीक हैं। सरकार तो पूंजीवादी व्यक्ति की सरकार है और गरीब मजदूर व किसानों की कोई सुननेवाली सरकार नहीं है।

एस्कोर्ट

फरीदाबाद की इस प्रमुख कम्पनी में पिछले साल मैनेजमेंट-यूनियन एग्रीमेंट से इनसैनटिव स्कीम शुरू की गई। वर्क लोड बढ़ाने वाली इस एग्रीमेन्ट के खिलाफ मजदूर चीखे-चिल्लाये और फिर गाली देकर दो पैसे कमाने की दौड़ में जुट गये।

इनसैनटिव की स्कीम ही ऐसी होती है कि मजदूर अन्धे होकर काम करते हैं। दस महीनों में ही एस्कोर्ट मजदूरों ने साल भर के प्रोडक्शन कोटे को पूरा कर दिया। इस पर नवम्बर के शुरू में सैकन्ड प्लान्ट में 5500 राजदूत मोटर साइकलों का स्टाक जमा हो गया। कम-बेशी यही हाल ट्रैक्टरों का है।

इस तरह ले आफ लगाने का सवाल मैनेजमेन्ट के एजेन्डे पर आ गया। पर मामला ले आफ तक का ही नहीं है कि स्लो डाउन से बात आई-गई हो जायेगी। पेन्शन आदि की अचानक माँग करके स्लो डाउन करवाना मजदूरों की आँखों पर परदा डालने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता।

एस्कोर्ट मजदूरों ने इनसैनटिव स्कीम के चक्कर में 10 महीनों में 12 महीनों का प्रोडक्शन देकर मैनेजमेंट को 25 परसैन्ट मजदूर एक्स्ट्रा होने की धारदार तलवार पकड़ा दी है। कब और कैसे यह तलवार मजदूरों के सिर काटेगी यह अभी साफ नहीं है पर शतरंज की एक चाल कुछ ऐसी हो सकती है : एग्रीमेंट पर दस्तखत के मुताबिक 1990 तक यूनियन कोई आर्थिक माँग नहीं उठायेगी। पेन्शन आदि साफ तौर पर आर्थिक माँग उठाकर यूनियन मैनेजमेंट को एग्रीमेंट तोड़ने का आधार दे। मैनेजमेंट एग्रीमेंट रद्द करे और यूनियन इसके खिलाफ हड़ताल करे। और तब छंटनी की तलवार···

ई० एस० आई० और मजदूर

इस व्यवस्था में मजदूरों को सुविधाएँ जब गिनाई जाती हैं तब ई० एस० आई० की चर्चा भी इस व्यवस्था के पक्षधर करते हैं। मजदूरों को सस्ता इलाज और एक्सीडैण्ट होने पर बीमा के नाम पर हर महीने उनकी तनखा में से ढाई परसैण्ट पैसे ई० एस० आई० के नाम पर कटते हैं और उतने ही पैसे मैनेजमेंट भी ई० एस० आई० को देती है। ठेकेदार और कई छोटे मालिक आमतौर पर फैक्ट्री कानूनों से बचने के लिये, ई० एस० आई० वाले पैसे बचाने के लिए और अक्सर ई० एस० आई० के नाम पर मजदूरों के वेतन से काटे पैसे भी अपनी जेब में रखने के लिए मजदूरों के नाम ई० एस० आई० में दर्ज नहीं करवाते।

यहाँ हम उन मजदूरों के बारे में बात करेंगे जिनके पास ई० एस० आई० कार्ड हैं। फरीदाबाद की गली-गली में बैठी प्राइवेट डाक्टरों की फौज एक तरफ जहाँ मजदूरों की सेहत की गवाह है वहीं दूसरी तरफ यह ई० एस० आई० के कामकाज की असलियत भी दिखाती है। ई० एस० आई० कार्ड वाले मजदूर प्राइवेट डाक्टरों के पास इसलिए नहीं जाते कि उनकी जेब में पैसे ज्यादा हैं, बल्कि ये प्रायवेट इलाज ई० एस० आई० के बुरे हाल से तंग आ कर ही करवाते हैं। ई० एस० आई० बजट का बड़ा हिस्सा तो बड़े अफसर चौपट कर देते हैं और बचे-खुचे में हिस्सा-पत्ती के चक्कर में छोटे अधिकारी भी रहते हैं। शामत आती है मजदूरों की। टाईम-ब-टाईम लीडर लोग हल्ला-गुल्ला करते हैं पर बदलता कुछ नहीं।

इन हालात से तंग आ कर ई० एस० आई० की ईस्ट इण्डिया डिस्पैन्सरी के नाम कार्ड वाले मजदूरों ने एक कदम उठाया है। अपनी परेशानियों को लिख कर, सात सौ से ज्यादा इन मजदूरों ने दस्तखत करके सी० एम० ओ० को ज्ञापन दिया। ईस्ट इण्डिया डिस्पैन्सरी में कुछ चुस्ती आई है। मजदूरों की छोटी-छोटी परेशानियाँ कम हुई हैं। अन्य मजदूरों को इन मजदूरों के इस कदम से सीखना चाहिए। मजदूरों द्वारा अपनी परेशानियों के खिलाफ मिलकर कदम उठाना जरूरीहै—इससे ही आगे की राहें खुलेंगीं। बिचौलियों-मसीहाओं पर आस लगाना मजदूरों की बरबादी की राह है।

गेडोर

इसका नाम अब झालानी टूल्स है। सात साल पहले ढाई करोड़ रुपये का बैंक से लोन लेकर मैनेजमेंट ने आटोमेशन की मशीनरी फिट की। डेढ़ हजार मजदूरों से मार-मार कर 1984 में इस्तीफे लिखवाये। लेकिन पाँच साल से स्विच दबाने भर के इन्तजार में खड़ी आटोमेशन मशीनरी आज तक चालू नहीं की गई है। लगता है 1985 में मैनेजमेंट को पता चला कि डेढ़ हजार मजदूर निकालने और आटोमेशन मशीनरी चालू करने के बाद भी यह धन्धा कोई ज्यादा फायदे का नहीं है और तबसे मैनेजमेंट अपनी झोली भरने में लगी है। मजदूरों की सर्विस, प्रोविडैण्ट फण्ड वेतन आदि का पैसा हो चाहे बैंक मैनेजरों की जेबों में पैसा डाल कर कम्पनी के नाम पर लिये जा रहे लोन हों—जहाँ से भी हो सकें, मैनेजमेंट पैसे बटोरने में लगी है। यही पिछले तीन साल से कम्पनी के रुक-रुक कर, गिरते-पड़ते चलने की असली कहानी है। और इस तथा उस डाइरेक्टर के झगड़ों की यही जड़ है। कम्पनी बीमार तो घोषित कर ही दी गई है, दिवालिया करके बन्द करने (क्लोजर) से पहले की लूट मैनेजमेंट ने मचा रखी है।

मैनेजमेंट-दल्लों-पुलिस-प्रशासन से छः साल से कुटते-पिटते गेडोर टूल्स के मजदूर टूट गये हैं। पर ऐसे में भी हाथ-पर-हाथ धरकर बैठने में तो मजदूरों का और कबाड़ा ही होगा। असलियत को समझना और कदम उठाना गेडोर मजदूरों के लिए जरूरी है।

थर्मल में स्वास्थ्य से खिलवाड़

फरीदाबाद थर्मल पावर हाउस सरकारी कारखाना है। हरियाणा बिजली बोर्ड यहाँ करीब 200 मेगावाट बिजली बनाता है। आधे से ज्यादा मजदूर यहाँ ठेके-दारों के हैं। अधिकतर जोखिम वाले काम ठेकेदारों के मजदूरों से करवाये जाते हैं।

बड़ी मात्रा में कोयला और राख थर्मल पावर हाउसों की खासियत है। इन जगहों पर कोयला और राख बहुत उड़ती है। सरकारी कानूनों के मुताबिक धूल-धूयें को कम करने के लिए कुछ संयन्त्र, सेफ्टी गार्ड लगाने जरूरी हैं। फरीदाबाद थर्मल में भी यह यन्त्र लगे हैं। परन्तु आमतौर पर यह सेफ्टी गार्ड बीमार रहते हैं। जब कोई चेक करने आता है तब उसे दिखाने भर के लिए इनमें से कुछ को चलाया जाता है। ठप्प पड़े सेफ्टी गार्ड कोल हैन्डलिंग प्लान्ट, कोल मिल और राख डिपार्ट (ई० पी० एम० पी०) में साफ-साफ देखे जा सकते हैं और तो और, रिपेयर में लापरवाही की वजह से ऑगजलरी बिल्डिंग के सामने मेन रास्ते पर ही 40 फुट की ऊँचाई से खुलेआम कोयला गिराया जाता है। इन कारणों से उठती राख और कोयले की आँधी ने वहाँ साँस लेना और देखना मुश्किल बना रखा है।

इन जगहों पर काम करने वाले मजदूर ज्यादातर ठेकेदारों के मजदूर हैं। ऐसे वातावरण में काम करने से उनका स्वास्थ्य जल्दी ही खराब हो जाता है। बीमार मजदूरों को निकाल कर ठेकेदार नए-नए मजदूर भरती करते हैं। यहाँ काम कर रहे परमानेन्ट मजदूर भी साँस की बीमारियों से परेशान हैं। उनमें से कई मजदूर अपने दर्द को भुलाने के लिए नशा करते हैं। थर्मल और उसके आस-पास काम काम करने वालों पर भी यह कोयला धूल बुरा असर डालती है। धूल-धूयें को कम करने वाले सेफ्टी गार्डों को वर्किंग में लाने के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मजदूरों द्वारा मिल कर कदम उठाने जरूरी हैं।

मैनेजमेंट का तो हाल यह है कि स्टीम छोड़ने के वक्त आधा-आधा घण्टा कान-फोड़ शोर थर्मल के आस-पास तक के लोगों को परेशान करता है जबकि साइ-लैंसर कई साल से स्टोर में आराम कर रहा है।

स्वत्वाधिकारी व सम्पादक शेरसिंह द्वारा आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद से प्रकाशित व अशोक कम्पोजिंग एजेंसी द्वारा, मानस प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली-110031 में मुद्रित